न्यायधीश राजीव नारायण रैना के सामने,

निखिल मदन-याचिकाकर्ता
बनाम
आईटीएम विश्वविद्यालय-उत्तरदाता

2011 का सीडब्ल्यूपी सं. 17048
30 मई 2012

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया और प्रवेश शुल्क का रिफंड जमा किया-इस बीच एक सरकारी कॉलेज में प्रवेश मिला-इसके बाद उसने प्रवेश के लिए कटऑफ तिथि से परे शुल्क के रिफंड के लिए आवेदन किया-रिफंड ने इनकार कर दिया-रिट याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि सीट का उपभोग किया गया था, क्योंकि कटऑफ तिथि के बाद उस सीट के खिलाफ किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जा सकता था-निजी कॉलेज छात्रों से एकत्र शुल्क और खाली सीट पर चलते हैं, एक देयता-रिलायंस ने प्रवेश नीति और चयन प्रक्रिया के खंड 27 पैरा 7 पर भी रखा।

माना जाता है कि यह एक व्यक्ति का एक बहुमूल्य अधिकार है कि वह वहाँ पढ़ाई करे जहाँ वह सोचता है कि भविष्य की संभावनाओं के लिए यह सबसे अच्छा संभव है। याचिकाकर्ता को दीन बधू सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज, मुरथल नामक एक प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए केवल उसकी पीठ पर थपथपाया जा सकता है। लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने जो सीट छोड़ी थी, वह कॉलेज की गलती के बिना खाली रह गई है। आईटीएम विश्वविद्यालय, जो वर्तमान मामले में प्रतिवादी है, को एक निजी डीम्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है। निजी कॉलेज शीर्ष वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित सीटों के स्वीकृत प्रवेश के स्रोत से एकत्र शुल्क पर चलाए जाते हैं, जिन पर कॉलेजों का बुनियादी ढांचे के अनुसार उपलब्ध सीटों की संख्या पर बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित किया जाना चाहिए और इस तरह के मामले में सहानुभूति के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है।

para 3

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ए. पी. भंडारी
सौरभ दलाल, प्रतिवादी के वकील

न्यायमूर्ति राजीव नारायण रायना

1. इस याचिका में प्रार्थना शुल्क की वापसी के लिए है। याचिकाकर्ता को 03/07/2010 को इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार शाखा में प्रतिवादी विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। उन्होंने आंशिक शुल्क के रूप में 87,500/- रुपये जमा किए। इसके बाद या27.7 है। "माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सक्षम प्राधिकारी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए कोई प्रवेश नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद वापसी के मामले में इसे खाली सीट के अनुसार मध्य पाठ्यक्रम वापसी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जो डिग्री के शेष वर्षों के लिए खाली रहेगी। इसे ध्यान में रखते हुए किसी भी मध्यावधि निकासी के मामले में किसी भी नाम से कोई शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाता है। "चिकाकर्ता को सरकारी कॉलेज में प्रवेश मिला और इसलिए उसने 29/09/2010 को सीट की खपत के खिलाफ अपना प्रवेश रद्द करने का अनुरोध किया। उनके अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय ने दिनांक 01/10/2010 के पत्र के माध्यम से निर्धारित किया कि प्रवेश की वापसी कट ऑफ तिथि के बाद थी और इसलिए विश्वविद्यालय को किसी अन्य छात्र को प्रवेश देने से वंचित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने अपनी प्रवेश नीति और चयन प्रक्रिया 2010-11 पर भरोसा किया। खंड 27 नियम 7 इस प्रकार हैः

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सक्षम प्राधिकारी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए कोई प्रवेश नहीं किया जा सकता है।इसलिए प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद वापसी के मामले में इसे खाली सीट के अनुसार मध्य पाठ्यक्रम वापसी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जो डिग्री के शेष वर्षों के लिए खाली रहेगी। इसे ध्यान में रखते हुए किसी भी मध्यावधि निकासी के मामले में किसी भी नाम से कोई शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाता है। "

2. विश्वविद्यालय के कानूनों में कहा गया है कि मध्यावधि प्रवेश नहीं किया जा सकता है और एनओसी तभी दी जा सकती है जब याचिकाकर्ता प्रवेश के समय प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार पूरी शेष राशि जमा कर दे। विश्वविद्यालय ने खंड 28 नियम 1 का आश्रय लिया जो नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

28 मिड कोर्स विदड्रॉल्स एडमिशन से

"चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा मध्य पाठ्यक्रम वापसी के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए कोई मध्य पाठ्यक्रम प्रवेश नहीं किया जा सकता है, इसलिए मध्य पाठ्यक्रम वापसी के लिए प्रवासन/स्थानांतरण प्रमाण पत्र का कोई आपत्ति प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र को प्रवेश के समय प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार शेष वर्ष शुल्क और विश्वविद्यालय को बकाया कोई अन्य बकाया जमा करने के बाद ही दिया जाएगा। "

3. यह एक व्यक्ति का एक बहुमूल्य अधिकार है कि वह वहाँ पढ़ाई करे जहाँ वह सोचता है कि भविष्य की संभावनाओं के लिए यह सबसे अच्छा संभव है। याचिकाकर्ता को दीन बधू सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज मुरथल नामक एक

प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए केवल उसकी पीठ पर थपथपाया जा सकता है। लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने जो सीट छोड़ी थी, वह कॉलेज की गलती के बिना खाली रह गई है। आईटीएम विश्वविद्यालय, जो वर्तमान मामले में प्रतिवादी है, को एक निजी डीम्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है। निजी कॉलेज शीर्ष वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित सीटों के स्वीकृत प्रवेश के स्रोत से एकत्र शुल्क पर चलाए जाते हैं, जिन पर कॉलेजों का बुनियादी ढांचे के अनुसार उपलब्ध सीटों की संख्या पर बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित किया जाना चाहिए और इस तरह के मामले में सहानुभूति के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। धनवापसी के नियमों के ढांचे के भीतर शुल्क की वापसी के मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा 2011 के सीडब्ल्यूपी 1133 में एल के तलवार और दूसरे बनाम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 09/05/2012 को निर्णय लिया गया है। निर्धारित प्रस्ताव याचिकाकर्ता के खिलाफ है जब यह मानता है किः

"यूजीसी के पत्र दिनांक 23/4/2007 के संदर्भ में धनवापसी का मामला उचित होगा यदि सीट का उपभोग किया जाता है और फिर कट ऑफ तिथि तक या उससे पहले किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा खाली किया जाता है, तो ही धनवापसी अधिकार का विषय बन सकता है। वर्तमान स्थिति अलग है। लिखित बयान में एक स्पष्ट पाठ है कि याचिकाकर्ता के पाठ्यक्रम छोड़ने के कारण जो सीट खाली हो गई थी, वह "पूरे शैक्षणिक सत्र और उसके बाद किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा नहीं भरी गई थी।" याचिकाकर्ताओं द्वारा तथ्य के इस कथन का खंडन करने के लिए कोई प्रतिकृति दायर नहीं की गई है। इसलिए बयान की सच्चाई पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। मेरे पास इस पर अविश्वास करने का कोई सांसारिक कारण नहीं है। प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पत्रों, दिशानिर्देशों, नीति परिपत्रों से बाध्य है। एक विशिष्ट नियम के सामने, श्री बजाज प्रस्तुत करते हैं कि आत्म प्रकाशित खट्टर में दिया गया निर्णय लागू नहीं होगा क्योंकि उस मामले में इसके विपरीत कोई नियम नहीं बनाया गया था और निर्णय नहीं लिया गया था। वास्तव में उस मामले में धन वापसी का कोई नियम नहीं था और मामले का निर्णय पहले सिद्धांतों पर किया गया था। घर के निकट, श्री बजाज इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 9711 के भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सोनीपत में अपने वाइस प्रिंसिपल बनाम हरियाणा स्टेट काउंसलिंग सोसाइटी और अन्य के माध्यम से 6/1/2012 को तय किए गए निर्णय पर भरोसा करते हैं, जिसमें यूजीसी के पत्र के समान प्रावधान को ए1सीटीई के शुल्क की वापसी के नियमों के रूप में निपटाया गया था। इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के माध्यम से बोलते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

"याचिकाकर्ता-कॉलेज के रुख के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 3 और 6 द्वारा खाली की गई सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं, इस तथ्य को आधिकारिक उत्तरदाताओं के साथ-साथ निजी उत्तरदाताओं द्वारा विवादित नहीं किया गया है। तदनुसार, एआईसीटीई मानदंडों के अनुरूप उत्तरदाता संख्या 3 से 6 द्वारा जमा किए गए प्रवेश शुल्क को वापस नहीं करने के याचिकाकर्ता-कॉलेज के रुख को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित इस मानदंड के पीछे एक

धारणा है कि कॉलेज विशेष रूप से गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज छात्रों से उनके द्वारा ली गई फीस पर चलते हैं। वे किसी भी स्रोत से सहायता पर निर्भर नहीं हैं और अपने अस्तित्व के लिए वे मुख्य रूप से उम्मीदवारों/छात्रों से एकत्र शुल्क पर निर्भर हैं... "

"मामले के इस दृष्टिकोण में, इस न्यायालय के लिए यह संभव नहीं है कि वह कोई भी निर्देश दे, जैसा कि कानून में या तथ्यों पर या नैतिक आधार पर, पवित्र जिम्मेदारी या पवित्र कर्तव्य के लिए अनुरोध किया गया है।"

4. इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री जतिंदर सिंह द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13308 2009 में आत्म प्रकाश खट्टर और अन्य बनाम हरियाणा सरकार के आयुक्त और सचिव और अन्य (पी-7) के रूप में निर्णय पर दी गई निर्भरता अच्छी तरह से योग्य नहीं है।

5. पूर्वगामी कारणों से, मुझे इस याचिका में ऐसा कोई गुण नहीं मिलता जो खारिज हो जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सूर्य करण चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)